



चौदास घाटी में उच्च मूल्य के औषधीय पादपों का संवर्धन एवं कृषिकरण

अमित बहुखंडी, कुलदीप जोशी एवं आई.डी. भट्ट

गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा

भारतीय हिमालयी क्षेत्र एक समृद्ध और उल्लेखनीय जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जो हिमालयन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्षेत्र लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (लंबाई में 3000 किमी और चौड़ाई में 250-300 किमी और ऊंचाई में 300 से 8000 मीटर) तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की समृद्ध वनस्पतियों में लगभग 18,440 विभिन्न पादप प्रजातियां पायी जाती हैं। जिनका उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा दवा, जंगली खाद्य, ईंधन, लकड़ी, आदि के रूप में किया जाता रहा है। इसके अलावा, हिमालयी क्षेत्र से लगभग 1748 पादप प्रजातियों को उनके औषधीय गुणों के आधार पर पहचान मिली है। वर्तमान में औषधीय पौधों को प्राकृतिक सक्रिय जैव रासायनिक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है तथा विभिन्न रोगों के उपचार हेतु पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में उपयोग किया रहा है। आज औषधीय पौधों की मांग हर्बल, कॉस्मेटिक, दवा उद्योगों द्वारा नई दवा खोज हेतु बढ़ती जा रही है। जिसके कारण हिमालयी क्षेत्रों से औषधीय प्रजातियों का व्यापार हेतु नियमित दोहन किया जा रहा है। वर्तमान में लगातार औषधीय प्रजातियों की बिना वैज्ञानिक तकनीक तथा

ज्ञान से कटाई, जानवरों द्वारा अनियमित चराई, उनके आवासों को नुकसान, जलवायु परिवर्तन और कई अन्य कारकों से विभिन्न औषधीय पौधों पर दबाव तथा विलुप्ति का संकट बढ़ गया है। साथ ही कई औषधीय प्रजातियों की जनसंख्या तथा उपलब्धता में गिरावट आई है तथा इनके संरक्षण हेतु पहल विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए औषधीय प्रजातियों की बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा खेती कर इस संकट को कम किया जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप हिमालयी प्रजातियों का संरक्षण तथा स्थानीय किसानों की आजीविका में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अतः गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा द्वारा हिमालयी अध्ययन राष्ट्रीय मिशन के तहत चौदास घाटी, पिथौरागढ़ जिले के चयनित गाँवों में सहभागीता के माध्यम से विविध औषधीय प्रजातियों जैसे एलियम स्ट्रैची (जम्बू), एंजेलिका ग्लौका (चोरु), सिनामोम तमाला (तेजपात), हेडिकियम स्पाईकेटम (वन हल्दी), पिक्चुरिजा कुरुवा (कुटकी), ससुरिया कोस्टस (कूट) और वेलेरियाना जटामांसी (तगर) की वृहद खेती में प्रयास किये जा रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, व्यापार हेतु औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा तथा प्रगतिशील किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हेतु कार्यान्वयन के लिए भागीदारी की पहल करना है। उक्त परियोजनाओं के तहत चौदास घाटी में विभिन्न कार्यशाला, औषधीय पादपों की व्यापारिक खेती तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसी बुनियादी संभावनाओं में आवश्यक सहयोग की दिशा में कार्य किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप चौदास क्षेत्र के कुल 172 किसानों ने 124.5 नाली (2.5 हेक्टेयर) भूमि पर लक्षित प्रजातियों की खेती शुरू की है। घाटी के प्रगतिशील किसानों द्वारा उच्च हिमालयी औषधीय प्रजातियों जैसे जम्बू, चोरु, वन हल्दी, कुटकी, कूट और तगर की व्यापारिक खेती उच्च ऊंचाई वाले गांवों (नियांग, पस्ती, सोसा, पलंगारी) में तथा तेजपात और तगर की खेती कम ऊंचाई वाले गांवों (जयकोट, पंगला और गरकू) में की जा रही है। साथ ही, श्री नारायण आश्रम को औषधीय प्रजातियों के प्रदर्शन स्थल के रूप में तैयार जा रहा है जिसमें लगभग 15 से अधिक उच्च मूल्य वाले हिमालयी औषधीय प्रजातियाँ जैसे की एलियम स्ट्रैची (जम्बू), एंजेलिका ग्लौका (चोरु), एकोनिटम हेट्रोफिलम (अतीस), हेडिकियम स्पाईकेटम (वनहल्दी), ओरिगेनम वल्गारी (वनतुलसी), पिक्चुरिजा कुरुवा (कुटकी), पोर्टेला फुलगेन्स (बज्रदन्ती), पेरिस पॉलीफाइला (सत्तू), पियोनिया इमोडी (चंद्रा), पोलिगनटमे वर्टिसिलटम (मेदा), पोलिगनटमे सिरिफोलैम (महामेदा), फाइटोलैक्का एकिनोसा (हिमालयन पोकरेरी), ससुरिया कोस्टस (कूट), रोसकिया प्रोसेरा (काकोली) और वेलेरियाना जटामांसी (तगर) संरक्षित हैं। साथ ही, किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदर्शन स्थल से समय समय पर कच्चा माल वितरित किया जाता है। संस्थान द्वारा प्रगतिशील किसानों को औषधीय पादपों की व्यापारिक खेती हेतु हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान (एचआरडीआई), गोपेश्वर में पंजीकृत तथा भविष्य में उत्पादित कच्चा माल खरीद हेतु विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों जैसे की सुरकुंडा जडी-बूटी समुह, बागेश्वर तथा हयूमैन इंडिया, श्रीनगर के साथ बायबैक व्यवस्था के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा विविध कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय विविध हितधारकों को जैव विविधता के संरक्षण, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने आदि संवेदनशील विविध विषयों पर जानकारी और सहयोग समय-समय पर प्रदान किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की सामुदायिक आजीविका में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अतः हिमालयी जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समुदाय विशेष की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि हिमालयी भू-क्षेत्रों में प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को मजबूती प्राप्त हो सके।



संयोजक संस्थान

गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की स्थापना सन 1988-89 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गयी। यह संस्थान संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने, एकीकृत प्रबंधन रणनीति बनाने व उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्रभाविता के प्रदर्शन और पर्यावरणीय दृष्टि से मजबूत प्रबंधन हेतु मुख्य संस्थान के रूप में चिन्हित है।

Coordinating institute

G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment was established in 1988-89 as an autonomous institute of Ministry of Environment Forest & Climate Change (MoEF & CC), Government of India. The institute has been identified as focal agency to advance scientific knowledge, evolve integrated management strategies, demonstrate their efficacy or conservation of natural resources, and ensure environmentally sound management in the entire Indian Himalayan region (IHR).



गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान

G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment

An autonomous institute of Ministry of Environment, Forest & Climate change (MoEF & CC, Government of India)

Kosi-Katarmal, Almora 263 643, Uttarakhand, INDIA

Web: <http://gbpihed.gov.in> | Phone: +91-5962-241015

For further detail, please contact:

Dr. Ranbeer S. Rawal, Director, National Project Coordinator- KSLCDI, India (psdlr@gbpihed.nic.in)

Dr. G.C.S. Negi, Scientist G, Nodal Person, KSLCDI, India (negiacs@gmail.com)

Er. M.S. Lodhi, Scientist E, Nodal Person, Hi-LIFE, India (mahesh29@mail@gmail.com)

Dr. Rajesh Joshi, Scientist E, Nodal Person- KL, India (dr.rajeshjoshi@gmail.com)

Guidance



Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

Facilitation and funding



Indian partners



भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

